(b) the sites out of thess which are dangerous;

(c) what is being done to protect the surrounding population from any accidents on these abandoned sites; and

(d) how many accidents have taken place on these sites during the last year?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF MINES (SHRI BALRAM SINGH YADAV): (a) to (d; The information till date has not been sent by the concerned State Governments. On receipt of the information, it will be placed on the Table of the House.

इस्पात कारखानों का आधुनिकीकरण

***187. श्रीमती सरला माहेश्वरी : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या देश में इस्पात कारखानों के आधुनिकीकरण के लिये रूस के साथ कोई बातचीत हुई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या रूस द्वारा भारत को आधुनिकतम इस्पात तकनीक दिये जाने की संभावनाओं पर भी उस देश के साथ कोई बातचीत हुई है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) जी, नहीं । आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों का आधुनिकीकरण करने के लिये कोई बातचीत नहीं हुई है । तथापि, रूसी, दुर्गापुर और राउरकेला इस्पात संयंत्रों के आधुनिकीकरण कार्य में अन्तर्राष्ट्रीय निविदा के आधार पर भाग ले रहे हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) इंडो-रसियन फेडरेशन ज्वाइंट कमीशन के उदघाटन-सत्र जो जून, 1994 में हुआ था, में अन्य बातों के साथ-साथ लौह तथा अलौह धातुओं के संबंध में कार्यदल गठित करने का निर्णय लिया गया । इस दल की अब तक कोई बैठक नहीं हुई है। तथापि, बातचीत के लिये सहयोग के निम्नलिखित क्षेत्रों का पता लगाया गया है:—

(i) प्रौद्योगिकी सहयोग जिसमें संयुक्त उद्यम भी शामिल है ।

(ii) वैज्ञानिकों/विशेषज्ञों का एक दूसरे के देश में दौरा ।

(iii) अनुसंधान और विकास (आर० एंड डी०) के क्षेत्र में सहयोग ।

अरबी मदरसों को अनुदान दिया जाना

*190. **श्री मोहम्मद मसूद खान :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य से मान्यता-प्राप्त अरबी मदरसों को अनुदान देने की केन्द्रीय सरकार की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो इसकी क्या-क्या शर्तें हैं, और

(ग) यदि इस प्रकार की कोई योजना नहीं है, तो उसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) राज्य से मान्यता प्राप्त अरबी स्कूलों को अनुदान देने के लिए भारत सरकार की कोई योजना नहीं है लेकिन प्राचीन भाषाओं, जिनमें अरबी भी शामिल है, के परिरक्षण और प्रोन्नति के लिए स्वैच्छिक संगठनों/संस्थाओं को अनुदान देने के लिए एक योजना है ।